



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 2012/श्रावण 4, 1934

No. 168]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 2012/SHRAVANA 4, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2012

सं. 12 (आर.ई. : 2012)/2009-2014

विषय : प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 (आर. ई. : 2012) 2009-14 में संशोधन ।

फा. सं. 01/91/180/160/एम-12/पीसी 3.—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 (आर. ई. : 2012)/2009-2014 के पैरा 2.13.2क, 3.6.1, 3.10.3, 3.11.7, 3.11.8, 4.19, 5.10 और 5.23 को तत्काल प्रभाव से संशोधित करते हैं। इसे 5-6-2012 से प्रभावी माना जाएगा।

2. पैरा 2.13.2क (क) के अन्त में वाक्यांश “अप्रयुक्त रहता है” जोड़ा गया है और संशोधित पैरा निम्नानुसार होगा:

“(क) यदि क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा 15.9.2011 को अथवा उससे पहले पृष्ठांकन किया गया है किन्तु पुनः क्रेडिट अप्रयुक्त रहता है।”

3. पैरा 3.6.1 के तहत (भारत से सेवित स्कीम के लिए अपात्र छूट और सेवाएँ) उप पैरा (छ) के बाद नया उप-पैरा (ज) जोड़ा गया है। नया उप-पैरा निम्नानुसार होगा:

“(ज) शिपिंग लाइन्स सेवा प्रदायकों द्वारा किसी देश एक्स से किसी देश वाई रुट से दी जाने वाली सेवाओं जो कि किसी भी रूप में भारत से होकर गुजरती नहीं है, के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन”

4. पैरा 3.10.3 (ख) को पुनः लिखा गया है ताकि नीति का गंतव्य स्पष्ट हो सके ।  
पुनः लिखा गया पैरा निम्नानुसार होगा:

“(ख) यदि आवेदक ने वर्ष 2010-11 अथवा 2011-12 अथवा 2012-13 के दौरान शुल्क ईपीसीजी प्राधिकार पत्र प्राप्त किया है तो वे उस वर्ष के लिए एस एच आई एस का पात्र नहीं होंगे [अर्थात् संगत पिछले वर्षों (क्रमशः 2009-10, 2010-11, 2011-12 के दौरान किए गए निर्यातों के लिए)] । ऐसे एस एच आई एस आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे और पैरा 9.3 (आवेदन प्रस्तुत करने में देरी के लिए विलम्ब कटौती) भी लागू नहीं होगा ।”

5. पैरा 3.11.7 के पहले वाक्य में शुल्क क्रेडिट स्क्रिप की वैधता अवधि 24 महीने के स्थान पर 18 महीने के रूप में संशोधित की जाती हैं । संशोधित पैरा निम्नानुसार होगा:

“शुल्क क्रेडिट स्क्रिप 18 महीने की अवधि के लिए वैध होगी। शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के पुनः वैधीकरण की अनुमति नहीं होगी जब तक प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 2.13.1 या पैरा 2.13.2क के अन्तर्गत शामिल न हों ।”

6. मौजूदा पैरा 3.11.8 नए पैरा द्वारा निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

3.11.8 (क) “मुक्त शिपिंग बिल श्रेणी के तहत प्रस्तुत किए गए निर्यात पोतलदानों के मुक्त शिपिंग लिए विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत लाभों का दावा करने हेतु बिलों पर आशय पात्र होने के लिए शिपिंग बिलों पर निम्नलिखित घोषणा पत्र की आवश्यकता की घोषणा होगी:

हम अध्याय 3 के तहत लाभों का दावा करना चाहते हैं ।

(ख) विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 (शुल्क वापसी सहित) अध्याय 5 अथवा अध्याय 6 की किसी भी स्कीम के तहत निर्यात पोतलदानों के लिए ऐसी उद्घोषणा आवश्यक नहीं होगी ।

(ग) यदि किसी नए उत्पाद अथवा नए बाजार को शामिल करने के लिए ऐसे लाभों को प्राप्त करने का निर्णय साथ-साथ या बाद में लिया जाता है, तब:-

(i) ऐसे उत्पादों का निर्यात करने के लिए/ऐसे बाजारों को निर्यात करने के लिए मुक्त पोतलदान बिलों पर इस आशय की घोषणा करने के लिए निर्णय/अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना की तिथि से एक महीने की छूट अवधि की अनुमति दी जाएगी ।

(ii) एक महीने की छूट अवधि के बाद, सभी निर्यातों (ऐसे उत्पादों अथवा ऐसे बाजारों को) को मुक्त पोतलदान बिलों पर इस आशय की उद्घोषणा शामिल करनी होगी ।

(iii) उत्पादों/बाजारों के निर्णय/अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना की तिथि से पहले किए गए निर्यातों के लिए, ऐसी उद्घोषणा आवश्यक नहीं होगी क्योंकि ऐसे निर्यात पहले ही किए जा चुके हैं ।

7. निम्नलिखित पत्तनों को "पंजीकरण का पत्तन" से संबंधित पैराग्राफ 4.19 में आईसीडी और समुद्री पत्तनों के अंत में जोड़ा जाएगा:-

आईसीडी:- तोंदियारपेट (टीएनपीएम) चैन्नई,

समुद्री पत्तन: कराईकाल (पुदुचेरी संघ शासित क्षेत्र)

इन नामों को संबंधित सूची के अंत में जोड़ा जाना है ।

(प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के संशोधित संस्करण में, इन्हें फिर क्रमवार तरीके से रखा जाएगा)

8. पैरा 5.10 के उप पैरा (क) और (ख) को संशोधित किया गया है और निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

(क) यदि जारी किए गए प्राधिकार पत्र का अधिक मूल्य के आयात के लिए वास्तविक रूप से उपयोग कर लिया गया है, जो लागत बीमा भाड़ा मूल्य/प्राधिकार की बचायी गई शुल्क राशि के 10% तक है तो प्राधिकार पत्र को यथा-अनुपात में बढ़ा दिया गया माना जायेगा। सीमाशुल्क प्राधिकारी संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पृष्ठांकन के बिना, प्राधिकार पत्र मूल्य/बचाई गई शुल्क राशि के 10 प्रतिशत तक अधिक, माल की निकासी की अनुमति स्वतः ही दे देगा ।

(ख) ऐसे मामले में, प्राधिकार-पत्र धारक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को किए जाने वाले अतिरिक्त आयातों के एक महीने के भीतर किए गए अतिरिक्त आयात को शामिल करने के लिए लागत बीमा भाड़ा मूल्य/बचाई गई शुल्क की राशि के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क देगा। निर्यात दायित्व स्वतः ही आनुपातिक रूप से बढ़ जाएगा ।

9. पैरा 5.23 (निर्यातोत्तर ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट स्ट्रिप) के उप पैरा (ख) और (छ) को संशोधित किया गया है तथा अब निम्नलिखित रूप से पढ़ा जाएगा:

“(ख) पूँजीगत वस्तुओं के आयात के लिए निर्यातक को सभी लागू होने वाले शुल्कों का नकद भुगतान करना होगा ।”

“(छ)(i) आगम बिल किए गए आयात पर भुगतान किए गए शुल्क को दर्शाता है। तत्पश्चात, यदि सेनवैट क्रेडिट प्राप्त कर लिया गया हो, तो उस पर ड्यूटी क्रेडिट स्ट्रिप प्रदान करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा । क्षेत्राधिकारी उत्पादशुल्क प्राधिकरण की यह घोषणा कि 'उसके इस आगम बिल(बिलों) पर सैनवैट क्रेडिट प्राप्त नहीं किया है तथा न ही वह "भविष्य" में प्राप्त करेगा' के प्रमाणपत्र के न होने पर सीवीडी घटक पर कोई ड्यूटी क्रेडिट स्ट्रिप प्रदान नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में जहाँ सी वी डी अंश की गणना ड्यूटी

क्रेडिट स्ट्रिप देने के लिए की जाती है, क्षेत्रीय प्राधिकारी इस संबंध में आगम बिल (बिलों) को पृष्ठांकित करेगा तथा यह भी उल्लेख करेगा कि सीवीडी अंश के लिए सैनवेट का लाभ नहीं लिया जाएगा तथा आगम बिल(बिलों) की संगत सूची सहित ब्यौरे देते हुए क्षेत्राधिकारी उत्पादशुल्क प्राधिकरण को एक पत्र भेजेगा।

(ii) तथापि, यदि (क) यूनिट उत्पादशुल्क के साथ पंजीकृत नहीं है अथवा (ख) यूनिट ने उत्पादशुल्क से बाहर रहने का विकल्प चुना है अथवा (ग) अन्तिम उत्पाद उत्पादशुल्क के अधीन नहीं है तो केन्द्रीय उत्पादशुल्क कार्यालय से ऐसे प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। ”

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 में कुछ संशोधन/आशोधन किए जा रहे हैं जिन्हें 05.06.2012 से लागू माना जाएगा।

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक विदेश व्यापार

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 26th July, 2012

No. 12 (RE : 2012)/2009-2014

**Subject : Amendment of IIBP Vol. I (RE : 2012)/2009-2014.**

**F. No. 01/91/180/160/AM-12/PC 3.**—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014 the Director General of Foreign Trade hereby amends para 2.13.2A, 3.6.1, 3.10.3, 3.11.7, 3.11.8, 4.19, 5.10 and 5.23 of the Handbook of Procedures Vol. I (RE : 2012)/2009-2014. This will be deemed to have come into effect on 5-6-2012.

**2. At the end of Para 2.13.2.A (a) phrase “remains unutilized” has been added and the revised para will be as under:**

*“(a) If the endorsement has been made by Regional Authority on or before 15.9.2011 but the re-credit remains unutilised”*

**3. In para 3.6.1(Ineligible Remittances and Services for SFIS) a new sub-para (h) is added after sub- para (g). The new sub-para will be as under:**

*“(h) Foreign Exchange earnings for Services provided by Shipping Lines Service Providers from plying from any country X to any country Y routes, not touching India at all.”*

4. Para 3.10.3 (b) is being rewritten to better reflect the intention of policy. The rewritten para will be as under:

"b) In case an applicant has availed Zero Duty EPCG Authorisation during the year 2010-11 or 2011-12 or 2012-13, they shall not be entitled to SHIS for that year [i.e. for export made during the respective previous years (2009-10, 2010-11, 2011-12)]. Such SHIS applications will be summarily rejected and para 9.3 (late cut for delay in filing application) shall also not be applicable."

5. Validity period of Duty Credit Scrip mentioned in the first sentence of para 3.11.7 is amended as 18 months in place of 24 months. The amended para will be as under:

"Duty Credit Scrip shall be valid for a period of 18 months. Revalidation of Duty Credit Scrip shall not be permitted unless covered under paragraph 2.13.1 or paragraph 2.13.2 A of HBP v1."

6. Existing para 3.11.8 would be replaced by a new para as under:

3.11.8 (a) "Export shipments filed under the Free Shipping Bill category, would need the following declaration on the Shipping Bills in order to be eligible for claiming benefits under chapter 3 of FTP:

**Declaration of Intent on Free Shipping Bills**

'We intend to claim benefits under Chapter 3.'

(b) Such declaration shall not be required for export shipments under any of the schemes of Chapter 4 (including drawback), Chapter 5 or Chapter 6 of FTP.

(c) If there is a decision subsequently / later to include any new product or new market to avail such benefit, then:

(i) For exports of such products/ export to such markets, a grace period of one month from the date of decision/ notification/public notice will be allowed for making this declaration of intent on free shipping bills.

(ii) After the grace period of one month, all exports (of such products or to such markets) would have to include the declaration of intent on the free shipping bills.

(iii) For exports made prior to date of decision/notification/public notice of products/markets, such a declaration will not be required since such exports would have already taken place."

27854/12-2

**7. The following Ports shall be added at the end of ICDs and Sea Ports in paragraph 4.19 related to "Port of Registration".**

ICDs: Tondiarpet (TNPM), Chennai,

Sea Ports: Karaikal (Union territory of Puducherry)

These names are to be added at the end of the respective list.

(In the revised edition of HBP vol. 1, names of these ports would be placed in correct alphabetical order)

**8. Sub-para (a) and (b) of Para 5.10 are amended and will be as under:**

- (a) If authorization issued has actually been utilized for import of a value in excess, upto 10% of CIF value /duty saved amount of authorization, authorization shall be deemed to have been enhanced by that proportion. Customs shall automatically allow clearance of goods in excess, upto 10% of authorization value/duty saved amount, without endorsement by concerned RA.*
- (b) In such case, authorization holder shall furnish additional fee to cover excess imports effected, in terms of CIF value/duty saved amount, to RA concerned, within one month of excess imports taking place. Export obligation shall automatically stand enhanced proportionately.*

**9. Sub-para (b) and (g) of Para 5.23 (Post Export EPCG Duty Credit Scrip) are amended and will be as under:**

- "(b) For importing Capital Goods, all applicable duties shall be paid in cash by the exporter."*
- "(g) (i) Bill of Entry indicates the duty paid on the import made. Subsequently, Cenvat Credit, if availed, shall not be taken into account for grant of duty credit scrip. In the absence of a certificate from the jurisdictional Central Excise Authority stating that 'Cenvat Credit on this Bill of Entry(ies) has not been availed and will not be availed in future' no duty credit scrip would be granted on the CVD component. In all cases where CVD portion is considered for grant of duty credit scrip, RA shall endorse the Bill of Entry(ies) to this effect, mentioning that CVD Portion shall not be Cenvatable and send a communication to the same jurisdictional Central Excise Authority informing the details along with relevant list of Bill of Entry(ies).*

*(ii) Such certificate from Central Excise shall, however, not be required in case (a) the unit is not registered with Central Excise, or (b) the unit has opted out of Central Excise net or (c) the end product is not subject to Central Excise duty."*

Effect of this Public Notice: Certain amendments/modifications in HBP Vol.1 are being made which will be deemed to have come into effect on 5.6.2012.

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade